

MR. SPEAKER: Mr. Deo, please listen to me. I tell you that this matter relates to the law and order of the State.

SHRI P. K. DEO: Sir, this is a breakdown of the Constitution. The death of Parsuram Satpathy, journalist was caused under the wheel of congress Jeep DHA 9836 driven by Juba Congress workers on 29th November 1974.

MR. SPEAKER: Again I tell you that this is a law and order problem which is the state subject.

SHRI P. K. DEO: Sir, from F.I.R. filed in Bolangir P.S. on 27th November 1974, we learn that on 24th November 1974 evening when Shri Parsuram Satpathy was coming, he met Shri Bikramananda Bohidar on the road.

MR. SPEAKER: Will you please sit down? This is a state matter.

SHRI P. K. DEO: He halted him and told him that his life was not safe and that he was passing this information secretly to Shri Satpathy that murderers from outside like Bombay and Calcutta might be brought to kill him. As Shri Bohidar is a member of the Congress Party there may be some truth. Please take necessary action and give protection.

MR. SPEAKER: Mr. DEO, this is a State matter I cannot allow you.

SHRI D. K. DEO: Sir, the conspiracy was hatched to kill him when Deputy Minister was present in Bolangir.

MR. SPEAKER: I tell you again that this is a state matter relating to the law and order of the State.

SHRI P. K. DEO: I only invite your attention to this that a calculated murder is committed. The jeep has been impounded and the Con-

gress workers have been arrested. May I request you to direct the Minister of Home Affairs to make a statement?

MR. SPEAKER: Kindly sit down. Why do you raise matters which concern the law and order of the State? You do not listen to me.

श्री मोहम्मद इस्माइल (बंरकपुर) :
अध्यक्ष जी, मैंने तीन दिन पहले मशन किया था (अवधान) मीटिंग के बाद हमारे आफिस को जला दिया गया दो बजे रात को 10 घादमी वहा पर थे। यह हो रहा है श्रीमती सतपथी के राज्य मे।

MR. SPEAKER: I have repeatedly told you all that this is not permissible

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Why do you interrupt the proceedings? Kindly sit down. You are not called. Now, Mr. Madhu Lumaye....

12.25 hrs.

RE. VIOLATION OF ARTICLE 284 OF THE CONSTITUTION

श्री मधु लुमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय यह मामला मैं विगत सत्र मे उठाना चाहता था, ले किन बारबार मन्ने कहा गया कि अभी नहीं बाद मे उठाइयेगा। यह मैं

सविधान की धारा 284 के तहत उठाना चाहता हूँ। इनमें यह कहा गया है

"284 All moneys received by or deposited with—

(a) any officer employed in connection with the affairs of the Union or of a State in his capacity as such, other than revenues or public moneys raised or received by the Government of India or the Government of the State, as the case may be, or

(b) any court within the territory of India to the credit of any cause, matter account of persons,

shall be paid into the public account of India or the public account of the State, as the case may be"

अध्यक्ष महोदय : सरकार के दो खाते होते हैं, एक कंसालीडेटेड फंड आफ इंडिया और कंसालीडेटेड फंड आफ दी स्टेट और दूसरा खाता पब्लिक अकाउन्ट आफ इंडिया और पब्लिक अकाउन्ट आफ डी स्टेट। अब राज्यों के मुख्य मंत्रियों की ओर प्रधान मंत्री को उन के रिलिफ फंड के लिए, ग्राइममिस्टर रिलिफ फंड और श्रीक मिनिस्टर रिलिफ फंड के नाम से, बहुत सारा पैसा मिलता है। और ऑडिटर जनरल के साथ इसके बारे में वेरा एक अच्छे से पत्र-व्यवहार चल रहा है। श्रीमती मृणाल बोरे, जो हमारे दल की

महाराष्ट्र असेम्बली में सदस्या हैं, उन का भी पत्र-व्यवहार चल रहा है। लेकिन अभी तक कोई सतोषजनक उत्तर हमें नहीं मिला। मैंने यह जानना चाहा कि क्या प्रधान मंत्री श्रीर मुख्य मंत्रियों का यह कर्तव्य नहीं है कि रिलिफ के नाम पर उन को जो पैसा मिलता है, पब्लिक अकाउन्ट होने के नाते, वह सारा रुपया पब्लिक अकाउन्ट आफ इंडिया या स्टेट के खाते में जमा होना चाहिए। अभी इन खातों का कोई हिसाब किताब पालियामेंट या विधान सभा के सामने नहीं दिया जाता है। यह कौड़ी की रकम होती है और सभी राज्यों और केन्द्र की रकम को अगर मिला दिया जाये तो अरब से भी ज्यादा ऊपर यह रकम चली जायेगी। सविधान लागू होने के बाद अभी भी इस के बारे में ऑडिटर जनरल सो रहे हैं। प्रधान मंत्री खुलामा करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं कई बार इस के बारे में नोटिस दे चुका हूँ। क्या आप ससचीय कार्य मंत्री को आदेश देंगे कि धारा 284 का जो 24 साल से उल्लंघन हो रहा है क्या इस उल्लंघन को रोकने के लिए कोई सफाई या स्पष्टीकरण मंत्री महोदय देंगे। अध्यक्ष मे पब्लिक अकाउन्ट आफ इंडिया, राज्य और केन्द्र के खातों में यह रुपया जमा होना चाहिए और उन का ऑडिटेड स्टेटमेंट आफ अकाउन्ट बजट के समय हम लोगों को मिलना चाहिए। कौड़ी रुपय का घोटाला इसमें हो रहा है।

MR SPEAKER. I am going to ask him